सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-27 अंक-3 7 से 21 फरवरी, 2012 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

देशभर में 14 मार्च के संसद अभियान की तैयारी जोरों पर

बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर सोशलिस्ट यूनिटि सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) की केन्द्रीय कमेटी के आह्वान पर 14 मार्च के संसद अभियान की तैयारी देश भर में जोरशोर से जारी है। विभिन्न राज्यों में किये गये प्रदर्शनों, सभाओं, हस्ताक्षर संग्रह आदि कार्यक्रमों के अब तक प्राप्त समाचारं संक्षेप में दिये जा रहे हैं।

केरल : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा 14 मार्च को संसद मार्च की तैयारी और प्रधानमंत्री को सौंपे जाने वाले मांग पत्र पर हस्ताक्षर अभियान जोरशोर से जारी है। केरल में सामूहिक हस्ताक्षर अभियान के साथ ही हर कार्यकर्ता ने 1000 हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य लिया है। वहाँ लोगों से सम्पर्क साधा जा रहा है, जगह-जगह बातचीत व राजनैतिक चर्चा-बहस हो रही है, इससे बहुत सारे लोग प्रेरित व प्रोत्साहित होकर चन्दा भी दे रहे हैं, लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, वे खुद भी अपनी पहल पर औरों से हस्ताक्षर करवाने के लिए मांगपत्र का फार्म लेकर जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक अभियान में समय देने के साथ-साथ व्यक्तिगत तौर पर भी सुबह-शाम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व समाज के अन्य लोगों के पास जाते हैं। इससे वे भी पार्टी के करीब आते जा रहे हैं।

केरल में हस्ताक्षर अभियान और नुक्कड़ नाटक के दृश्य

इस देशव्यापी आन्दोलन की मुनादी करते हुए केरल के एकदम उत्तरी हिस्से के कसरागोडु जिले के होसानगडी से एक जत्था पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड के. राधाकृष्ण द्वारा झण्डी दिखाये जाने पर 23 जनवरी को रवाना हुआ है। यह रास्ते में पड़ने वाली जगहों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवा रहा है, 'यूनिटी' के विशेषांक सहित साहित्य बिक्री कर रहा है और जगह-जगह जनसभाएं करता जा रहा है। जनवरी महीने में इसने 4 जिले कवर कर लिए थे जिनमें दो जिलों में सीपीएम का जोर है। वहाँ हमारी पार्टी की गतिविधियाँ हालाँकि नई-नई शुरू हुई हैं और संगठन अभी सापेक्षत: छोटा है। लेकिन वहाँ जबरदस्त रेस्पोन्स मिला। तीसरा जिला वायनाड था जहाँ किसानों की खुदकुशी की दर्दनाक घटनायें घटती रही हैं। पार्टी ने वहाँ कृषक प्रतिरोध समिति बनायी है और कई प्रतिरोध आन्दोलन चलाये हैं। पार्टी द्वारा किसानों के जो मुद्दे उठाये हैं उन पर उनका भावुकता से भरा प्रत्युत्तर मिला।

40 स्थाई सदस्यों के इस जत्थे में शामिल पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड्स वी. वेणुगोपाल, जयसन जोजफ, एस. राजीवन, शैला के. जॉन, मिनी के. फिलिप, वर्घीज थॉमस जगह-जगह जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं। जत्था जिस जिले में प्रवेश करता है तो वहाँ के कॉमरेड भी काफी संख्या में उसमें शामिल हो जाते हैं। मेहनतकश लोगों की दयनीय हालत की थीम को लेकर एक नुक्कड़ नाटक मण्डली भी जत्थे के साथ चल रही है। जत्था केरल के सभी जिलों का दौरा करेगा और 25 फरवरी को त्रिवेन्द्रम में रैली के साथ इसका समापन होगा।

कर्नाटक : 14 मार्च को संसद चलो आन्दोलन के लिए चलाये जा रहे प्रचार अभियान के हिस्से के तौर पर कर्नाटक के तटीय जिले दक्षिण कन्नड़ में जिला स्तर पर दो दिवसीय जत्थे का आयोजन किया गया। यह जत्था 27 जनवरी को पुत्तुर से शुरू हुआ और बिठल, बी.सी. रोड़, मुदाबिदरी, सूरतकल और जिला

(शेष पृष्ठ 8 पर)

कर्नाटक : कॉ. जयालक्ष्मी लोगों को सम्बोधित करते हुए और नुक्कड़ नाटक का एक दृश्य

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की 28 फरवरी की हड़ताल को एस.यू.सी.आई.(सी.) का समर्थन

सोशलिस्ट यूनिटि सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉ. प्रभाष घोष ने तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा आहूत 28 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल का अपनी पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन किया है। यह हड़ताल ट्रेड यूनियनों के दीर्घलंबित मांग पत्र को मनवाने के लिए की जा रही है। इसमें अन्य बातों के अलावा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने, असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की खातिर पर्याप्त धन मुहैया कराने, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने, केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने, स्थाई प्रकृति के कामों का ठेकेदारीकरण रोकने, अनुसूचित रोजगारों का भेदभाव किए बिना सबको संवैधानिक न्यूनतम वेतन प्रदान करने तथा सभी को गारण्टीशुदा पेन्शन देने इत्यादि माँगें शामिल हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कॉमरेड प्रभाष घोष ने कहा: ''हमने पहले ही अपने पार्टी संगठनों को सभी स्तर पर 28 फरवरी को होने वाली देशव्यापी आम हड़ताल में दृढ़ एकजुटता के साथ शामिल होने का निर्देश दिया हुआ है। शासक पूँजीपति वर्ग और इसकी ताबेदार सरकारों द्वारा लागू की जा रही घोर जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी नीतियों के चलते मेहनतकश जनता का जीवन पूर्ण विनाश के कगार पर पहुँच चुका है। जिन पूँजीवादी भूमण्डलीकरण की नीतियों को केन्द्रीय व सभी राज्य सरकारों द्वारा दो दशकों से भी ज्यादा अर्से से आक्रामक तौर पर लागू किया जा रहा है उनसे स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसने वास्तव में ही हमारी जनता के सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक- सांस्कृतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में कहर बरपा दिया है। रोजगारों, रोजगार के अवसरों और संघर्षों से अर्जित अधिकारों पर बेरोकटोक हमले जारी हैं। कॉरपोरट घरानों के स्वार्थ में सरकार द्वारा प्रायोजित 'हायर एण्ड फायर' की नीति की तलवार सभी रोजगारों पर लटकी हुई है। जो भी थोड़ी-बहुत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बची हुई थी वह भी दाव पर लगी है। गैर-अंशदायी और डिफाइण्ड बेनिफिट आधारित पेंशन व्यवस्था का अधिकार छीन लिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। इन खतरनाक हालात में हम जनता के सभी तबकों का आह्वान करते हैं कि वे 28 फरवरी को होने वाली हड़ताल को कारगर ढंग से सफल बनाएं और मूलभूत अधिकार के रूप में काम का अधिकार, सरकार और मालिकों द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा देने, नई पेंशन व्यवस्था को रद्द करने, आवश्यक वस्तुओं की समग्र स्टेट-ट्रेडिंग चालू करने, सभी प्रकार की निजीकरण और विनिवेश प्रक्रिया को वापस लेने और सभी क्षेत्रों में ठेके पर या ठेकेदारों के माध्यम से काम पर लगाए गए लाखों मजदूरों को पक्का करने की माँगों को लेकर अपने संघर्ष को और भी तेज करें''

प्रधानमंत्री को सौंपे जाने वाले मांगपत्र पर अपने हस्ताक्षर करें

● बेतहाशा बढ़ती महंगाई ● खाद-बीज-कीटनाशकों की मूल्य वृद्धि ● बेरोकटोक पास करने की प्रथा ● जनवादी अधिकारों के हनन ● सीमाहीन भ्रष्टाचार ● महिलाओं व बच्चों की खरीद-बेच ● महिलाओं पर बढ़ते जुल्म-अत्याचारों के खिलाफ और ● रोजगार का मौलिक अधिकार ● सभी बेरोजगारों व छंटनी किये हुए मजदूर-कर्मचारियों को काम ● फसल के वाजिब दाम और ● सबको मुफ्त इलाज देने की मांग के लिए

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा 14 मार्च को संसद पर प्रदर्शन में शामिल हों

रांची में बस्ती बचाओ आन्दोलन

बस्ती बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जनसभा का आयोजन

झारखण्ड की राजधानी राँची में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ लगातार चलाये जा रहे आन्दोलन के क्रम में विगत 28 जनवरी को बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में बस्तीवासियों के अलावा कई बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभा को मुख्य रूप से प्रख्यात समाजसेवी मेधा पाटकर, बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक एवं एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के राँची जिला सचिव कॉमरेड सिद्धेश्वर सिंह, केया डे, विनय कुमार, मिन्टू पासवान आदि लोगों ने सम्बोधित किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि राँची के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विस्थापित अपने अधिकार के लिए हर पल सजग रहें। हक के लिए एकजुट होकर हर हाल में संघर्ष करें । उद्योगपतियों की नजर उनकी जमीन पर है। जमीन का दाम दिन ब दिन बढ़ रहा है और यह बाजार बन गया है। इसलिए जमीन से गरीबों को उजाड़ने की साजिश हो रही है। आज देश में पूँजीपतियों, बिल्डरों, अधिकारियों एवं राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक अलग तरह का गठबंधन देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि आज देश में विस्थापन की समस्या विकराल हो गई है। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए आन्दोलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि जमीन कोई पूँजीपतियों की जागीर नहीं है कि जब चाहे ले लें। जमीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार को शहरों में बस्ती सभा और गाँव में ग्राम सभा की सहमति लेनी चाहिए।

संस्थापक केया डे ने कहा कि लाखों गरीबों को कुचलकर चन्द अमीरों के हित में विकास की बात हो तो हम इसका विरोध करते आये हैं और करते रहेंगे। हम लड़ते आये हैं, लड़ते रहेंगे। गरीबों व आम जनता की हक की इस लड़ाई को बुल्डोजरों या मुकदमे का डर दिखाकर दबाया नहीं जा सकता। जब तक यहाँ पर सभी लोगों को इसी जमीन का मालिकाना हक न मिल जाए तब तक यह आन्दोलन जारी रहेगा। कॉ. सिद्धेश्वर सिहं ने सर्वप्रथम बस्ती बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना के समय से लेकर अब तक समिति द्वारा संगठित आन्दोलनों की विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर आशा तिर्की, रेशमी तिर्की, सूरजमणी तिर्की, अनिमा मिंज, बुधराम मुंडा, आदि लोगों ने कई जनवादी गीत पेश किये।

महान लेनिन जिन्दाबाद

''निम्न-पूंजीवादी जनवादियों ने, वर्ग-संघर्ष को वर्ग-सामन्जस्य वेफ सपनों में देखने वालों ने, समाजवादी रूपांतर को भी स्वप्निल ढंग से शोषक वर्ग के प्रभुत्व वेफ विस्थापन के रूप में नहीं, बल्कि अपने कार्यभारों को समझ चुकने वाले बहुमत के आगे अल्पमत द्वारा शांतिपूर्ण आत्म-समर्पण के रूप में देखा। राज्य की वर्गोपरीयता की मान्यता के साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध यह निम्न पूंजीवादी कल्पना व्यवहार में मेहनतकश वर्गों के हितों के साथ गद्दारी का करण बनी, जैसा कि, उदाहरण के लिए, 1848 और 1871 की फ्रांसीसी क्रांतियों के इतिहास ने, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के शुरू में इंगलैण्ड, फ्रांस, इटली तथा अन्य देशों के अन्दर पूंजीवादी मंत्रिमण्डलों में ''समाजवादियों'' की शिरकत से यह गद्दारी जाहिर भी हुई है।

लेनिन

राज्य और क्रांति

सरकार की जनविरोधी नीतियों ने देश को भ्रष्टाचार और महंगाई के गर्त में धकेल दिया

रेवाड़ी में सभा को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के सांसद कॉ. तरुण मण्डल

रेवाड़ी: 20 जनवरी 2012, आशा कार्यकर्ता यूनियन, मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन एवं भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन संबंधित ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. के तत्वावधान में स्थानीय राव तुलाराम पार्क में विशाल रैली का आयोजन किया गया। मंच संचालन हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के महासचिव सूबेसिंह यादव व जे.पी.ए. के नेता शेरसिंह ने किया। रैली में हजारों की संख्या में आशा वर्करों, मिड डे मील वर्करों और भवन निर्माण कारीगर मजदूरों ने हिस्सा लिया। एस.यू.सी.आई.(सी.) के सांसद डॉ. तरुण मण्डल रैली के मुख्य वक्ता थे। डॉ. मण्डल ने कहा कि सरकार की नीतियाँ, पूँजीपतियों के स्वार्थ में हैं। सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते देश का अवाम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं सरकार आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, भवन निर्माण में जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति बेरुखापन अपना रही है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स को कम से कम 5,500 रुपए प्रतिमाह मेहनताना दिया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिकों के हक में कानून बनाया जाए, इत्यादि मांगों को लेकर आप अपना आन्दोलन और भी तेज करें और मैं आपके आन्दोलन की गूँज भारत की संसद में उठाऊँगा। ऑल इण्डिया यू.टी.यू.सी. के नेता कॉमरेड राजेन्द्र ने कहा कि यह रैली इस बात का सबूत है कि आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स एवं भवन निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की आवाज को लम्बे समय तक दबाया नहीं जा सकता।

रैली में भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के नेता बलराम यादव, अतरसिंह, सीताराम, राजबीर, धर्मवीर, आशा कार्यकर्त्ता यूनियन की नेता सुरस्ती, शारदा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैल्पर यूनियन की नेता पुष्पा दयाल, कृष्णा यादव तथा सैकड़ों वकीलों एवं अन्य प्रबुद्ध नागरिकों ने भी हिस्सा लिया।

पंजाब में कन्वेन्शन

कन्वेन्शन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड प्रताप सामल

बुढ़लाडा : पूंजीवादी शोषण-जुल्म के खिलाफ 22 जनवरी को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की ओर से यहाँ एक कन्वेन्शन आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के पंजाब राज्य प्रभारी कॉमरेड अमिन्दर पाल सिंह ने की। कन्वेन्शन के मुख्य वक्ता थे पार्टी के दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉमरेड प्रताप सामल। कॉमरेड सामल ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी आदि समस्याओं का मूल कारण मौजूदा शोषणमूलक पूंजीवादी व्यवस्था है जो मरणासन्न को चुकी है और गहरी आर्थिक मंदी में फंसी हुई है। अमेरिका के वाल स्ट्रीट आन्दोलन जैसे दुनिया भर में चल रहे आन्दोलनों को उन्होंने पूंजीवाद फेल हो जाने का परिणाम बताया। उन्होंने 14 मार्च को दिल्ली में संसद पर पार्टी द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और प्रधानमंत्री को दिये जाने वाले मांग पत्र पर चल रहे हस्ताक्षर अभियान को तेज करने की अपील की।

कॉमरेड अमिन्दर पाल सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पंजाब के चुनावी परिदृश्य पर रोशनी डालते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशाखोरी और सांस्कृतिक पतन को बढ़ावा देना शासक वर्ग की साजिश है। उन्नत नीति-नैतिकता व मूल्यबोधों के आधार पर जोरदार जनवादी जनआन्दोलन का प्रतिज्वार पैदा करके इसे नाकाम करना होगा। कन्वेन्शन में कॉमरेड्स जसबीर कौर, मनजीत कोटरा, भास्करानन्द, थाना सिंह, इन्दर सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। कन्वेन्शन का मंच संचालन कॉमरेड बलविन्दर ने किया।

एआईडीएसओ, झारखण्ड राज्य कमेटी द्वारा आयोजित शिक्षण शिविर को सम्बोधित करते हुए संगठन के महासचिव कॉ. सौरभ मुखर्जी

यू.पी. विधानसभा चुनाव

जातिवाद व साम्पंदायिकता का दैत्य जनजीवन के ज्वलंत मुद्दों पर हावी

उत्तर प्रदेश व अन्य चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यू.पी. में, जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव परिणामों और राजनैतिक हालात का भारत की सियासी बिसात पर बहुत बड़ा असर पड़ता है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ लगता हिन्दी भाषी एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इसलिए यहां के चुनाव से पहले के हालात का जायजा लेने, ताकतों का जोड़-तोड़ बिठाने और भावी चुनावी नतीजों की अटकलें लगाने पर सब की नजरें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा अखरने वाली बात यह लग रही है कि कोई भी पूंजीवादी, निम्न पूंजीवादी पार्टी और तथाकथित मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओं को अपने एजेण्डे के तौर पर उठाने के मूड में नहीं है। इसकी बजाय वे स्थानीय या प्रदेश स्तर पर घोर निन्दनीय और दंगे भड़काऊ जातिवाद-साम्प्रदायिकता और मौकापरस्त सिद्धांतहीन जोड़-तोड़ पर आधारित अपने चुनावी गणित हल करने में लगी हुई हैं। साफ जाहिर है कि जातपात को अपने राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों को अड़ंगी मारने के लिए लाया गया है। फिलहाल इस या उस जाति के लिए, इस या उस धर्म-समुदाय के लिए आरक्षण दिलाने को लेकर इनमें एक-दूसरी से होड़ लगी हुई है ताकि इन लाइनों पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। यहां तक बुर्जुआ मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग, विश्लेषणों व पैनल चर्चाओं में इन्हीं मुद्दों को उछाल रहा है मानो वोट की प्राथमिकताएं तय करने में सिर्फ यही चीजें महत्वपूर्ण हों। केवल एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ही है जो एक वैकल्पिक लाइन – हर जाति, धर्म-समुदाय, इलाके या नस्ल के शोषित-पीड़ितों के जीवन में तमाम दुख-तकलीफों, कंगाली और बदहाली को पनपाने वाली सड़ी-गली मरणासन्न पूंजीवादी व्यवस्था को साफ तौर पर बढ़ावा देने वाली और हर तरह की फूट डालने वाली तिकड़मों से ऊपर उठकर जनता की ज्वलन्त मांगों पर दीर्घस्थायी एकताबद्ध जोरदार जनवादी आन्दोलन खड़ा करने की लाइन पर चुनाव लड़ रही है।

प्रमुख पार्टियों का राजनैतिक कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी पूंजीवादी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के अलावा मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी(एसपी) और मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख दावेदार पार्टियां हैं। दरअसल, पिछले दो दशकों से ज्यादातर समय सरकार या तो समाजवादी पार्टी या बीएसपी की रही है। शासक भारतीय पूंजीपति वर्ग की सबसे ज्यादा भरोसेमंद पार्टी कांग्रेस ने आजादी के बाद चार दशक तक उत्तर प्रदेश में एकछत्र शासन किया था और किसी दुर्जेय विपक्ष की गैर मौजूदगी में विभिन्न जातिवादी व धार्मिक समीकरणों को हैण्डल करते हुए फायदा उठाया था। लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों व नेताओं के कुशासन और अपना-अपना घर भरने के साथ-साथ जबरदस्त आर्थिक व राजनैतिक शोषण से हिन्दी भाषी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनमानस में बड़ा भारी रोष जमा हो गया था, खासकर उनमें जो सबसे पिछड़े और दलित समुदायों से थे जो घोर पूंजीवादी शोषण-उत्पीड़न के शिकार थे। इस मौके का फायदा उठाकर घोर हिन्दू-साम्प्रदायिक दल बीजेपी चालाकी से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा देते हुए एक विकल्प के तौर पर उभर कर आई और इसने 1990 के दशक के शुरूआती दौर में कांग्रेस को सरकारी गद्दी से हटाते हुए धूमकेतु जैसा उभार दर्ज कराया था। सत्ता पर काबिज होने के लिए इसने खुली साम्प्रदायिक राजनीति करते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला और हिन्दू वोट बटोरने के लिए हिन्दू धर्मान्धता व कट्टरता को उकसाया। चुनावी फायदा उठाने के लिए साम्प्रदायिक लाइन पर लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी नेताओं ने जाहिर है कि अपने आका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कहने पर ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को ढहाने के घोर घिनौने काम को सरअंजाम दिया था। निस्संदेह इससे जहां तक सत्ता पर काबिज होने का सवाल है उन्हें जरूर फायदा मिला लेकिन देश भर में सही सोच-समझ रखने वाले लोगों ने इसे एक बर्बर कार्रवाई करार देते हुए इसकी तीव्र निन्दा की। इस आपराधिक कार्रवाई की देशव्यापी निन्दा को देखकर बीजेपी नेताओं ने अपने साम्प्रदायिक घाट से अपनी दूरी बनाने का दिखावा किया ताकि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक गैर-साम्प्रदायिक जनसाधारण को रिझाया जा सके। लेकिन उन्होंने न तो अपने साम्प्रदायिक रुख-रवैये के लिए कोई माफी मांगी और न ही अपना हिन्दुत्व का नुकसानदेह एजेण्डा छोड़ा जिसका सबूत है गुजरात का बीभत्स कत्लेआम। चूंकि यू.पी. में शोषक वर्ग का काफी सारा हिस्सा, जैसे कि कुलक यानी धनी किसान और बड़े व्यापारी जिन्हें बीजेपी की इस साम्प्रदायिक राजनीति से फायदा हुआ और वोटों का पलड़ा भारी करने में एक निर्णयक भूमिका निभाते हैं वे इन तथाकथित सवर्ण जातियों ब्राह्मण या राजपूत समुदायों के हैं। इस प्रदेश में जातिगत आधार पर वोट पड़ने पर बीजेपी वोट बटोरने में इस खास समुदाय पर अच्छा असर रखती है। चुनावी दृश्य पर हावी रहे और आबादी के शोषित-पीड़ित निचले तबके को नतमस्तक होने के लिए डराने-धमकाने के लिए दहशत फैलाते रहे शोषकों का यह समूह इससे पहले कांग्रेस का साथ देता था। लेकिन बाद में जब देखा कि कांग्रेस अपनी लोकप्रियता तेजी से गवांती जा रही है, तो वे कांग्रेस का साथ छोड़ कर बीजेपी के वफादार बन गये जिसमें उनको एक वैकल्पिक शक्ति नजर आई जो उनके संकीर्ण वर्ग स्वार्थों को पूरा करेगी। यू.पी. के चुनाव सिर पर आते ही बीजेपी धनी किसानों और बड़े व्यापारियों की इस ताकतवर लॉबी की कृपापात्र बनने की हर सम्भव कोशिश करने में जुट गई और साथ ही राज्य के जातपातवादी-साम्प्रदायिक राजनैतिक माहौल के गंदे कड़ाहे में पक रही एक सम्भावित साम्प्रदायिक फूट का फायदा उठाने के लिए अपनी हिन्दुत्ववादी पहचान को सहेजने लगी। सबसे ज्यादा गौरतलब यह है कि हालाँकि शुरूआत में एक 'पार्टी विद ए डिफ्रेंस' का प्रभामण्डल तैयार कर लिया था और कांग्रेस के कुशासन से आजिज आ चुकी जनता को कुछ हद तक भ्रमित करने में सफल हो गई थी, लेकिन इसका जनविरोधी चरित्र उस समय बेनकाब हो गया जब यह सत्तारूढ़ हुई और इसने तत्परता से जनविरोधी, पूंजीपतिपरस्त नीतियाँ अपनायी। जनता को यह अगर कांग्रेस से भी खराब नहीं तो उससे बेहतर भी नजर नहीं आई। इससे बीजेपी का जनाधार घट गया। लेकिन बीजेपी से मोहभंग बाद में एक और खतरे को लाया। साम्प्रदायिकता की जगह एक और नया दानव, जातपात का उभार हो गया, जैसे कि एसपी और बीएसपी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया। ये दोनों पार्टियाँ जो अब यू.पी. में सत्ता की कुर्सी के लिए मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं बदतरीन किस्म की फूटपरस्त जातिवादी राजनीति के बुरे कर्म करने में मशगूल हैं। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और अच्छी-खासी मुस्लिम आबादी के वोटों पर निर्भर है। इस बार भी यह विरोधी खेमे के कुछ और मजबूत गढ़ों से समर्थन झटक लेने के अलावा उन वोट बैंकों पर अपनी पकड़ बनाये रखने की अपनी कोशिश में है। बीएसपी जो 1994 में अपने दलित हितैषी चेहरे मोहरे को लेकर बनी थी अगर सवर्णों के खिलाफ नफरत नहीं तो सवर्ण-विरोधी भावनाएं भड़का कर एक प्रमुख ताकत के तौर पर उभर आने का एक दशक के अन्दर जुगाड़ बैठा लिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2002 में मुख्यमंत्री बनने के लिए सवर्णों की मित्र पार्टी के तौर पर जानी जाने वाली बीजेपी से हाथ मिलाने में भी नहीं झिझकी थी। हालाँकि उनके 40 एमएलए दलबदल कर समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाने से उन्हें बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने प्रतिद्वंद्वी मुलायम सिंह को काबिज होने दिया था। 2007 के चुनावों में हालाँकि उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और फिर सत्ता की कुर्सी पा ली थी। उन्होंने ओबीसी और सवर्णों के प्रबल प्रभाव वाले क्षेत्रों में कुछ दबंगों और वोट मैनेजरों को कुछ माले-मुफ्त और हैसियत वाले ओहदे पेश करके वहाँ भी चतुराई से कुछ विधानसभा सीटें हथियाने की जुगत बिठा ली थी और इस तरह उन तबकों में अपनी कुछ पैंठ बना ली थी। दरअसल, ओबीसी और तथाकथित उच्च जाति वाले लोगों की वोटों के एक हिस्से ने 2007 में दलित-ब्राह्मण की अनौखी धुरी बनाने के लिए मायावती को पूरा समर्थन दे दिया था जिसने उन्हें सत्ता पर पहुंचाया था। सवर्णों में दबंगों के लिए बीजेपी से मोहभंग और मुलायम सिंह को सत्ता से हटाने की बदहवास कोशिश में यूं कहें कि बीएसपी एकदम 'फिट' थी। इस बार भी वे मुख्य तौर पर परम्परागत ढंग से दलित भावनाओं पर उछल रही हैं और इसके साथ-साथ कुर्सी बचाये रखने के लिए दूसरे तबकों के प्रति भी दोस्ती का हावभाव दिखा रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जिसकी वस्तुतः राज्य की वोट की राजनीति में कोई हस्ती ही नहीं बची थी क्योंकि बीजेपी और फिर सपा-बीएसपी उभर आई थी, मुस्लिमों के साथ-साथ दलितों के एक हिस्से का, दलितों में कुर्मियों व मुस्लिमों का दिल फिर सें जीतने की अपनी कोशिशों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। वहाँ कांग्रेस को फिर से जिन्दा करने का काम राहुल गाँधी को सौंपा गया है। इसलिए उन्हें टीवी व प्रिन्ट मीडिया में अक्सर दलितों के घरों में खाना खाते या छोटे बच्चों को गोद में उठाये हुए, जबरन भूमि हथियाने के खिलाफ पदयात्रा करते या सूखाग्रस्त उपेक्षित बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करते दिखया जाता है। सपा-बीएसपी के जाति आधारित मजबूत गढ़ों से कुछ वोट झटक लेने के आखरी मिनट के प्रयास में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियाँ दलितों व ओबीसी वालों को सब्जबाग दिखाकर उनके प्रति दोस्ताना हावभाव दिखाने की भी कोशिश कर रही हैं।

प्रदेश का खौफनाक मंजर

जहाँ ये वोट के पंछी जातिगत व साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण पर आधारित चुनावी गणित हल करने में लगे हैं, वहीं दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी लोग आकाश छूती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, छंटनी, लेऑफ, तालाबंदी, कृषि पैदावारों की गैर वाजिब दामों पर खरीद, गहराते कर्जजाल, इलाज व शिक्षा की कमी, बिजली-पानी की किल्लत व अन्य बहुत सारी समस्याओं के चलते तबाह हो रहे हैं जिन समस्याओं को शासक वर्ग और केन्द्र व राज्य में इसकी ताबेदार सरकारें न केवल पैदा करती जा रही हैं बल्कि आये दिन बढ़ाती जा रही हैं। असल में चाहे साक्षरता हो या शिशु मृत्यु या बेरोजगारी हो, सामाजिक विकास के हर सूचकांक पर उत्तर प्रदेश का दर्जा भारत में सबसे निचले पायदान पर है, इस तथ्य से हालात और भी खराब हो गये हैं कि महिलाओं से सम्बन्धित आँकड़े पुरुषों के मुकाबले हर लिहाज से काफी कम हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और बेहद उपजाऊ खेतीलायक जमीन वाले प्रदेश में बेरोजगारी की दर जुलाई 2009 और जून 2010 के बीच बहुत ज्यादा दर्ज की गई है। नेशनल सेम्पल सर्वे श्रमशक्ति भागेदारी की दर या आबादी के मुकाबले श्रमशक्ति के अनुपात, श्रमिकों की आबादी (प्रति 1000 व्यक्तियों में से रोजगारशुदा व्यक्तियों की संख्या), बेरोजगारों और रोजगारशुदा लोगों की दर के अनुपात (श्रमशक्ति के मुकाबले बेरोजगारों के अनुपात) के अग्रणी सूचकांकों को परिभाषित करता है। इस सर्वेक्षण द्वारा जुटायी गई जानकारियों के अनुसार यू.पी. में श्रमशक्ति भागेदारी की दर जुलाई 2009 और जून 2010 के दौरान 296 दर्ज की गई थी। यह बिहार से ज्यादा थी जहाँ यह प्रति 1000 व्यक्तियों

(शेष पृष्ठ 4 पर)

यूपी विधानसभा चुनाव...

(पृष्ठ 3 का शेष)

पर 276 दर्ज की गई थी। कम विकास के सागर में डुबे यू.पी. में योजना आयोग के 61वें नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसकी 17 करोड़ 50 लाख आबादी में से 44 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। भारत में गरीबों में से 20 प्रतिशत अकेले यू.पी. में रहते हैं, अनुमान है कि ये दुनियाभर के गरीबों का 9 प्रतिशत बैठते हैं। राज्य पर न के घोर गरीबी का बोझ है बल्कि वंचनाओं के अन्य सूचकांकों में ही नहीं, यहाँ तक कि अनेक अहम मानव विकास सूचकांकों में भी भारतीय राज्यों में यू.पी. का दर्जा बहुत निचले पायदान पर है। गत अप्रैल में मायावती सरकार को मानना पड़ा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) को लागू करने में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं। यहाँ तक कि स्टेट केबिनेट सक्रेटरी ने भी यह कबूल किया था कि एनआरएचएम स्कीम के कार्यान्वन में विभिन्न स्तर पर 3000 करोड़ रुपये का सरेआम भ्रष्टाचार हुआ था जिस में लखनऊ में परिवार कल्याण विभाग के दो चीफ मेडिकल अफसरों, डॉ. वी के आर्य और डॉ. बी पी सिंह का कत्ल एक पर एक हुआ था। पानी की भरमार वाले इलाकों में भी पेयजल की इतनी बड़ी भारी समस्या है कि एक दुखी आदमी यह टिप्पणी किये बिना नहीं रह सका, ''यू.पी. की मौजूदा सरकार जनता के निचले तबकों की सरकार कही जाती है... लेकिन गरीब लोगों की समस्याओं से निपटने के उनके तरीके ने साबित कर दिया है कि ये नेता दलितों के नेता बिल्कुल नहीं है और राज्य के गरीबों की इन्हें कोई फिक्र नहीं है। हालाँकि, चुनाव के समय राज्य की राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए वोट पाने की खातिर यही नेता गरीबों का बड़ा नाम लेते हैं।... जिस सरकार ने हाल ही में विधानसभा सदस्यों को वेतन-भत्ते 25,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देने वाली सरकार के पास राज्य के गरीब लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए कोई फण्ड नहीं है। ऐसा लोकतंत्र रखने के लिए हम शर्मसार हैं।'' सरकार ने न्यूनतम जरा अच्छा देने के लिए तो कुछ किया नहीं जबकि छीनने और लूटने की जादुई करामात खूब दिखाई है। निर्माणाधीन दो एक्सप्रेस हाईवे के साथ लगते 23,000 से ज्यादा गाँवों को सरकार विकास के निष्कंटक रास्ते जबरन हटाने पर उतारू है। यह न केवल राज्य के जमीनी नजारे को बदल कर रख देगा और यू.पी. के इन सबसे ज्यादा उपजाऊ भागों में ये बहुत सारे गाँव आते हैं बल्कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण भी उजड़ जायेंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये सब तो पानी में डुबे हिमशैल की सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाली चोटी के समान है। पूरी दास्तान धोखाधड़ी, वंचना, जुल्म-अत्याचार, दमन-उत्पीड़न की है।

कौन कहाँ खड़ा है

लेकिन आम आदमी की इस बदहाली और दुख-तकलीफ भरी हालत की किसी संसदीय पार्टी को कोई फिक्र नहीं है। जनता से कट कर और उनकी समस्याओं के प्रति बेरुखी के चलते इन वोट बटोरू संसदीय पार्टियों की जरा भी साख नहीं बची है। उल्टे ये दागी हैं, भ्रष्टाचार में आकण्ठ डुबी हुई हैं और पूरी तरह बदनाम हैं। ज्यादातर विधायक और चुनाव मैदान में उतारे गये इनके उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, उन पर मुकदमें चल रहे हैं। विधायिका असल में माफियाओं, गुण्डे-बदमाशों और सिद्धांतहीन लोगों का अड्डा बन कर रह गई है। पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस को ही ले लीजिए। जनविरोधी नीतियों के दौरों और ढेर सारे बड़े-बड़े घोटालों व भ्रष्टाचार के मामलों ने इस पार्टी की छवि बेहद धूमिल करके रख दी है। काफी हैरतअंगेज बात है कि यही कांग्रेस यू.पी. में मायावती सरकार को भ्रष्टाचार के लिए कोस रही है। यू.पी. में कांग्रेस पर कोई आदमी भरोसा नहीं करता है। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि कांग्रेस पार्टी यू.पी. में सरकार बनाने के कहीं आसपास भी है। यह भांप कर कांग्रेसी नेताओं ने अजीत सिंह के आरएलडी से गठबंधन किया है जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली ग्रामीण साधनसम्पन्न वर्ग में कुछ जनाधार है। चुनावोपरांत समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने की सम्भावना की बात भी उछाली जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस सम्भावना को खारिज नहीं किया गया है। कांग्रेस पर घातक हमले करते हुए अपनी छवि दोबारा चमकाने की फिराक में बीजेपी भी अपने बुने हुए जाल में खुद फंस गई है जब इसके अखिल भारतीय अध्यक्ष बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपी पूर्व बीएसपी मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और बादशाह सिंह को बीजेपी में शामिल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाये। सीट बंटवारे को लेकर हुए मतभेद के चलते इसका सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटिड) भी साथ छोड़ गया है। मुलायम सिंह और उनकी समाजवादी पार्टी सरकार-विरोधी जन भावना के बूते पर अपनी चुनावी वैतरणी पार करने का हिसाब लगा रही है हालाँकि इसके दिग्गज नेता और संसदीय राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी अमर सिंह इस पार्टी को छोड़ चुके हैं। खबर है कि मुलायम सिंह अन्दरखाने कांग्रेस से मिलीभगत से काम ले रहे हैं।

मायावती हुकूमत की दास्तान

एक तरफ तो मायावती और उनकी बीएसपी ने पिछले विधानसभा चुनावों से पहले जो छवि सजायी-संवारी थी वह काफी हद तक धूमिल हो गई है। मायावती सत्ता और धन की अपनी भूख को कोई रहस्य नहीं बनाती है। वे अपने अनुयायियों और शुभचिन्तकों से अपने जन्म दिन समारोह पर तोहफे के तौर पर पैसा लेती हैं। चुनावों में वे ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने वालों को टिकट बेचकर पैसा लेती हैं। विभिन्न परियोजनाओं और स्कीमों में उनके द्वारा पैसा लिये जाने के आरोप उन पर लगे हैं। तबादले और नियुक्तियाँ सत्ताधारी व्यक्तियों के लिए भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हर किसी को याद होगा कि उनके खिलाफ सीबीआई ने 30 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति नाजायज तरीके से प्राप्त करने के मामले में एक चार्जसीट तैयार की थी। बाद में 175 करोड़ रुपये के विवादित ताज हेरिटेज कोरीडोर प्रोजैक्ट के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उनके कई परिसरों पर छापे भी मारे गये थे। लेकिन हर कोई हैरत में पड़ गया जब उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले यह घोषणा की कि कांग्रेस ने उनसे इस सौदेबाजी की पेशकश की है कि अगर बीएसपी चुनावों के बाद कांग्रेस से गठजोड़ करने पर राजी हो जाये तो उनके खिलाफ सुनिश्चित रूप से कोई बेइन्साफी नहीं होने दी जाएगी। जबकि उन्होंने तो यह खुलासा नहीं किया कि सौदेबाजी किस बात को लेकर होनी थी, लेकिन यह साफ जाहिर है कि सन्दर्भ ताज कोरीडोर घोटाले और आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामलों का ही था। बाद में सीबीआई ने इन केसों की फाइल बंद करने का फैसला लिया था। अप्रैल, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी खण्डपीठों को ताज कोरीडोर केस में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से रोका था। इस तरह, जैसे ही वे शासक वर्ग के फरमान मानने को राजी हो गई वैसे ही विवदों की बरस रही आग बुझा दी गई और शासक वर्ग की सरपरस्ती से वह सत्तारूढ़ हुई। उनकी व्यक्तिगत धन-दौलत दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही, जबकि घोर गरीबी राज्य के लोगों को असहनीय दुख-तकलीफों की तरफ धकेल रही है। अप्रैल, 2007 में विधानसभा चुनावों के दौरान अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय मायावती ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा 52 करोड़ रुपये घोषित किया था। आकलन वर्ष 2008-2009 के लिए अपनी आयकर रिटर्न जमा कराते समय उन्होंने अपनी आय का अनुमान 60 करोड़ रुपये लगाया था और अग्रिम कर के रूप में 15 करोड़ रुपये आयकर भरा था। इस वित्त वर्ष के अन्त में असली आय इस अनुमान को पार कर गयी थी। वे देश की सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री घोषित की गई हैं।

चुनावों से पहले से ही मायावती और उनकी हुकूमत पर मुख्यमंत्री और उनके प्रिय पात्रों द्वारा सरेआम प्रदर्शित 'बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार' और 'भाई-भतीजावाद' को लेकर निशाना साधा जा रहा है। पार्टी के कई विधायकों और सांसदों पर कत्ल, बलात्कार, अपहरण, धन के गबन जैसी आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे हैं। सरकारी खजाने यानी जनता के पैसों से सैकड़ों करोड़ रुपये प्रदेश भर में मायावती की मूर्तियाँ लगाने पर खर्च कर दिये गये हैं। दिल्ली के साथ लगते नोयडा में 680 करोड़ रुपये की लागत से दलित प्रेरणास्थल बनाया गया है। वहाँ मायावती और बीएसपी के संस्थापक दिवंगत कांसीराम की दो कास्य प्रतिमाओं के अलावा 52 हाथियों की मूर्तियाँ हैं क्योंकि हाथी बीएसपी का चुनाव चिन्ह है। गंगा एक्सप्रैस हाईवे और जमना एक्सप्रैस हाईवे के नाम पर काफी सारी मात्रा में कृषि भूमि जबरन अधिग्रहित की गई है। इसके विरोध में जब लोग उठ खड़े हुए तो सरकार ने उन पर अंधाधुंध लाठी-गोलियाँ बरसाई। किसानों ने कोछोना, मिर्जापुर, अलीगढ़, भट्ठा-परसोल व अन्य जगहों पर जोरदार आन्दोलन खड़े किये हैं। पुलिस की गोलियों ने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है। कोई नया उद्योग नहीं लगा है। पहले से लगे हुए कई कारखाने बंद हो गये हैं। कभी तेजी से फैलता जाने वाला औद्योगिक शहर कानपुर आजकल विरान सा नजर आता है। बिजली उत्पादन में तेजी से गिरावट के चलते कृषि और उद्योग, दोनों ही क्षेत्र बड़ी भारी समस्या से गुजर रहे हैं। लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाने का भी विरोध किया है और वे विरोध की आवाज को दबाने के मद्देनजर रैली-प्रदर्शनों पर रोक लगाने के सरकार के फैसले के भी खिलाफ हैं। मायावती ने अपने पिछले पाँच साल के शासनकाल के दौरान लोगों को लगातार मुसीबतों में डालने और लाखों-लाख लोगों की भूख पर फलने-फूलने की बदौलत अपना जनाधार काफी हद तक खो दिया है। उनके खिलाफ शिकवे-शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी पार्टियाँ भी पूरी तरह बदनाम हैं। लोगों का ध्यान दूसरी तरफ फेरने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को चार छोटे-छोटे प्रदेशों में बांटने का एक प्रस्ताव विधानसभा में हाल ही पास कराया है मानो वह लोगों को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रोटी-कपड़ा-मकान -शिक्षा-स्वास्थ्य- साफसफाई-वाटर सप्लाई की समस्याओं, और उपराष्ट्रीय दमन, जातपात के झगड़ों व भेदभाव और ऐसे ही अन्य जुल्मो-सितम की सामाजिक बुराइयों से निजात दिला देगा। सीपीएम-सीपीआई जैसी नकली मार्क्सवादी पार्टियों समेत बाकी लगभग सभी पार्टियों ने इस कदम का समर्थन किया है जिसे सही ठहराने का कोई तुक नहीं है। इस विघटन का एकमात्र मकसद है लोगों में और भी फूट डालना जो प्रदेश में तमाम जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकताबद्ध जन आन्दोलन को कमजोर करेगा। कुछ ही साल पहले उत्तर प्रदेश से काट कर अलग राज्य उत्तराखण्ड बनाया गया था। क्या उससे लोगों की दुख-तकलीफें जरा भी कम हुई हैं या और भी घनघोर हुई हैं? लोगों की दुख-तकलीफों की तरफ से आँखें मूंदे बैठी रहने का मायावती का क्या औचित्य बनता है जो मुख्यमंत्री की गद्दी का दुरुपयोग करते हुए अपने वारे न्यारे कर रही हैं और वोट बटोरने के लिए खुद को दलित बता कर बेचारे गरीब लोगों को छल रही हैं?

आरक्षण का कार्ड

ये सब पार्टियाँ जानती हैं कि लोगों के मुद्दे उठा कर वे वोट व समर्थन नहीं माँग सकती हैं। इसलिए फूटपरस्ती भड़काने में उनके लगातार संलिप्त रहने की वजह से वे इस विधानसभा चुनाव की वेला में भी आरक्षण का कार्ड खेल रही हैं। चुनाव की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश में पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में आरक्षण का कोटा और भी बढ़ाने की अपने को पक्षधर

(शेष पृष्ठ 7 पर)

उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

भुवनेश्वर(उड़ीसा) : उपजाऊ कृषि भूमि को पोस्को, मित्तल, स्टर्लाइट, जे. आर. पॉवर, सी.एल.टी., उत्तम गालवा, वेदान्ता युनिवर्सिटी, वेदान्ता अल्युमिना आदि कम्पनियों के मालिकों समेत देशी-विदेशी पूँजीपतियों के हवाले करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों हजार प्रदर्शनकारियों ने 12 जनवरी को भुवनेश्वर में उड़ीसा सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार से माँग की कि इन कम्पनियों के साथ किए गए करार को तुरन्त रद्द किया जाए। 'कृषि जमीन, जल व परिवेश सुरक्षा अभियान, उड़ीसा' के बैनर तले बच्चों, महिलाओं, किसानों और खेतिहर मजदूरों ने भारी संख्या में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लोअर पी.एम.जी. चौक तक जुलूस निकाला। सशस्त्र सुरक्षा बलों ने प्रदर्शकारियों को पी.एम.जी. चौक से बहुत पहले ही रोक दिया जो सत्तासीन सरकार के नितांत जनविरोधी रवैये को दर्शाता है। सरकार इस या उस बहाने से लोगों के विरोध की आवाज को दबाना चाहती है।

'कृषि जमीन, जल व परिवेश सुरक्षा अभियान, उड़ीसा' के संयोजक और मित्तल प्रतिरोध मोर्चा के सलाहकार कॉमरेड रघुनाथ दास की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। मित्तल प्रतिरोध मार्चा के अध्यक्ष मुरलीधर सरदार, स्टर्लाइट-विरोधी मोर्चा के सलाहकार पुरुषोत्तम बेहरा और इसके सचिव मधुसूदन साहू, उत्तम गालवा-विरोधी जनमंच के अध्यक्ष पूरन चन्द्र साहू, पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के वासूदेव खंडवाल, सिद्धेश्वर आंचलिक सुरक्षा कमेटी, नराज के जोगेन्द्रा गरनायक, जीवन जीविका कृषि जमी सुरक्षा कमेटी, किशोरनगर, अंगुल के रमणी रंजन प्रधान, कृषक ओ कृषि जमीन सुरक्षा कमेटी, दुर्गापुर, अंगुल के केदार नाथ प्रधान, उपकुल भीटा माटी सुरक्षा कमेटी के अरुण जेना, मंदाकिनी कोयला खान क्षतिग्रस्त जीवन-जीविका कमेटी, कुकुदिया, अंगुल के नन्द ज्योतिष ने राज्य व केन्द्र सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया और लोगों से आह्वान किया कि वे कृषि भूमि और अपने जीवन-जीविका को बचाने के लिए लामबंद होकर प्रतिरोध आन्दोलन का निर्माण करें।

'नन्दीग्राम भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी' के बहादुर नेता कॉ. नन्द पात्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में सभा को सम्बोधित करते हुए अपनी 'भीटा माटी' को बचाने के लिए नन्दीग्राम के किसानों द्वारा किए गए सफल बहादुराना संघर्ष का वर्णन किया। उन्होंने उड़ीसा के लोगों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल से किसानों की 'भीटा माटी' को बचाने के लिए संघर्ष के सही रास्ते पर संयुक्त आन्दोलन का निर्माण करें।

इस विरोध सभा में डॉक्टर विरेन्द्र नायक, डॉ. एल.पी. सिंह, एडवोकेट प्रमोद प्रधान, सर्वश्री बृज मोहन मिश्रा, अक्षयदास, प्रफुल्ल सामंत, शम्भुनाथ नायक, गुरू मोहन्ती जैसी जानी मानी हस्तियों ने राज्य व केन्द्र सरकार दोनों की गलत औद्योगिक तथा कृषि नीति की आलोचना की। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कृषि भूमि, जल, खनिजों और पर्यावरण को बचाने के लिए किसानों और जनता के अन्य तबकों का संयुक्त आन्दोलन गठित करें।

पूर्व विधायक कॉ. शम्भुनाथ नायक के नेतृत्व में गुरू मोहन्ती, लक्ष्मीधर मोहन्ता, लघुराम सोरेन, सुनील कुमार सोरेन, दीनबन्धु प्रधान को लेकर बने एक प्रतिनिधि मण्डल ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें करार को रद्द करने की माँग की गई ताकि कृषि भूमि, जल संसाधनों और पर्यावरण को बचाया जा सके।

मजदूर सम्मेलन आयोजित

सूरत, गुजरात : 22 फरवरी को शहर के मध्य कांजीभाई देसाई हॉल में वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 'मजदूर सम्मेलन' किया गया। शहर के कोने-कोने से आए मजदूरों ने इसमें शिरकत की। एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉ. शंकर शाहा सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन की अध्यक्षता एस.यू.सी.आई(सी) के राज्य सचिव कॉ. द्वारिकानाथ रथ ने की। सम्मेलन की शुरूआत में वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन सचिव कॉ. नवलकुमार झा ने यहाँ के मजदूरों की समस्या को सविस्तार सभा के समक्ष रखा। सम्मेलन में उपस्थित मजदूरों ने बारी-बारी से अपनी बात रखी। अन्त में मुख्य वक्तव्य पेश करते हुए ए.आई.यू.टी.यू.सी. के महासचिव कॉ. शंकर शाहा ने श्रमिक वर्ग की दशा व दिशा को सविस्तार सभा के समक्ष रखा। वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सूरत के मजदूरों की स्थिति को लेकर एक 'सर्वेक्षण रिपोर्ट' भी निकाली गई।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लेबर यूनियन (भेलू) का द्विवार्षिक सम्मेलन

भोपाल : यहाँ भेल के फाउण्ड्री गेट चबूतरे पर 29 जनवरी को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लेबर यूनियन (भेलू) सम्बद्ध ऑल इण्डिया यूटीयूसी का वार्षिक सम्मेलन व चुनाव सम्पन्न हुआ। इसमें कॉमरेड्स लोकेश शर्मा को अध्यक्ष, के. पी. द्विवेदी व एस.के. वर्मा को उपाध्यक्ष, जे.सी. बराई को महासचिव, बी.एल. मौर्य व के.के. सूर्यवंशी को सचिव व आर.सी. स्वर्णकार को कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्यों को चुना गया।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए ऑल इण्डिया यूटीयूसी के सर्वभारतीय सचिव कॉ. आर.के. शर्मा ने भेल के ठेकाकरण और निजीकरण के खिलाफ जोरदार आन्दोलन छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने 28 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल को भी सफल बनाने की अपील की। सभा को यूनियन के अध्यक्ष कॉ. लोकेश शर्मा, उपाध्यक्ष के.पी. द्विवेदी, महासचिव जे.सी बारई आदि ने भी सम्बोधित किया।

यू-स्पेशल बसों की कमी व कैम्पस बसों में भाड़ा वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन

31 जनवरी 2012 को दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आये छात्रों ने ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले यू-स्पेशल बसों की कमी, कैम्पस बस सेवा की भाड़ा वृद्धि के खिलाफ और इनमें व दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए रियायती पास चालू करने की माँग पर प्रदर्शन किया और परिवहन मंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी छात्र आईटीओ चौक पर इकट्ठा हुए। दिल्ली सचिवालय की ओर बढ़ने से पुलिस के द्वारा रोक दिये जाने पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने उसी जगह एक प्रतिवाद सभा की।

सभा को संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड भास्करानन्द, राज्य सचिव कॉ. प्रशान्त कुमार, उपाध्यक्ष कॉमरेड दीपक रंजन, सत्यवती कॉलेज (मॉर्निंग) से संगम कुमार, सत्यवती कॉलेज (सांध्य) से कृष्णेन्दु मुखर्जी, हिन्दू कॉलेज से नीरज कुमार, जाकिर हुसैन कॉलेज से रुखसाना एवं कॉ. आसिफ, रामजस कॉलेज से आनन्द आदि ने सम्बोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि यू-स्पेशल बसें केवल नाममात्र का ही रह गई हैं जिससे छात्रों को कॉलेज आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असुरक्षित यातायात के कारण कई छात्रों की दुर्घटना में मौत तक हो चुकी है। कैम्पस में शुरू की गई बस सेवा में छात्रों के लिए रियायत बस पास लागू करने के बजाय बस का किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है जो आम बसों के किराये से भी महंगा है। परिवहन मंत्रालय का यह रवैया छात्र-विरोधी है। ज्ञापन में अविलम्ब पर्याप्त यू-स्पेशल बसें चलाने, कैम्पस बस सेवा के बढ़े किराये को वापस लेने, इसमें व मेट्रो में भी छात्रों के लिए रियायती पास लागू करने की माँग की गई। परिवहन मंत्री के ओ.एस.डी. श्री गुलाटी ने छात्रों की माँगों की तुरन्त सुनवाई के लिए दिल्ली परिवहन निगम के शिड्यूल्ड एण्ड प्लानिंग डिपार्टमेन्ट को आदेश दिया।

एम एस युनिवर्सिटी, वडोदरा में छात्र आन्दोलन की जीत, फीस वृद्धि पर लगी रोक

कलानगरी वड़ोदरा की विख्यात एम. एस. युनिवर्सिटी में 13 जनवरी को हुई सिन्डीकेट बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला यह कि युनिवर्सिटी के पन्द्रह वर्ष के इतिहास में 100% कमरतोड़ फीस वृद्धि की जाए तथा दूसरा यह कि युनिवर्सिटी के विद्यार्थी नेता वाइस प्रेसिडेन्ट, युनिवर्सिटी जनरल सेक्रेटरी तथा फेकेल्टी जनरल सेक्रेटरी को क्रमशः 1000 रुपये और 500 रुपये मासिक मानदेय वेतन दिया जाए।

ए.आई.डी.एस.ओ. द्वारा 16 जनवरी को इन दोनों निर्णयों का जबरदस्त विरोध किया गया तथा प्रतिनिधि मण्डल ने वाइस चान्सलर को आवेदन पत्र सुपुर्द करते हुए कहा कि शिक्षा के विकास के लिए जनता पहले से ही राज्य सरकार को शिक्षा-कर देती है तो शिक्षा के विकास के लिए भी युनिवर्सिटी को राज्य सरकार से सहायता लेनी चाहिए वरना इस तरह से फीस बढ़ाने से तो काफी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।

एम.एस.युनिवर्सिटी के संस्थापक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ मुफ्त शिक्षा में विश्वास रखते थे। हॉल ही में सयाजीराव की 150वीं जन्म जयन्ती चल रही है और आज उनके सपनों को भुलाया जा रहा है। सयाजीराव की 150वीं जयन्ती के अवसर पर ये कैसी भेंट? इसके साथ ही विद्यार्थी नेताओं को वेतन देकर वे विद्यार्थी आन्दोलन को कमजोर कर उन्हें पिट्ठू बनाना चाहते हैं। इसलिए छात्र नेताओं को वेतन देना निन्दनीय है।

आवेदन पत्र के परिणामस्वरूप अगले ही दिन वी.सी. को अपना निर्णय स्थगित करना पड़ा तथा उन्होंने दोबारा विचार करने का आश्वासन दिया और फिलहाल फीस वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 115वीं जयन्ती सम्मानपूर्वक मनाई गई

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड मैनेजर चौरसिया

दिल्ली : एआईडीवाईओ की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 115 जयंती के अवसर पर दिल्ली के कई इलाकों में उद्धरण व फोटो प्रदर्शनी तथा जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 26 जनवरी को मुकुंदपुर क्षेत्र में फोटो व उद्धरण प्रदर्शनी व जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संगठन के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉ. राकेश कुमार, सचिव मंडल सदस्य कॉ. रामबदन, संगठन की दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रकाश देवी तथा एसयूसीआई (सी) के दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य कॉ. मैनेजर चौरसिया ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी का जीवन-संघर्ष वर्तमान समय में भी नौजवानों को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरणा देता है। आज समाज में व्याप्त बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी, अपसंस्कृति, नशाखोरी के खिलाफ नौजवानों को आगे आना होगा और आंदोलन निर्मित करना होगा क्योंकि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। नेताजी का गैरसमझौतावादी संघर्ष आज भी हमें दिशा दिखाता है।

20 जनवरी को शालीमार बाग क्षेत्र में एआईडीवाईओ तथा एआईएमएसएस की ओर से फोटो व उद्धरण प्रदर्शनी तथा सभा की गई जिसे एसयूसीआई (सी) दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन एआईएमएसएस की वरिष्ठ सदस्या कॉ. नीतू खन्ना ने किया। सभा को कॉ. पी.के. पवार ने भी सम्बोधित किया। 29 जनवरी को संगठन की कोटला इकाई की ओर से कोटला क्षेत्र में फोटो व उद्धरण प्रदर्शनी लगाई गई।

लोनी (गाजियाबाद, उ.प्र.) : 22 जनवरी को यहां एक सभा आयोजित की गई जिसमें काफी संख्या में छात्र-नौजवानों ने हिस्सा लिया। सभा की शुरूआत क्रान्तिकारी गीतों से हुई। सभा के मुख्य वक्ता एसयुसीआई (कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड आर.के शर्मा थे। उनके अलावा कॉमरेड्स रवीन्द्र, शैलेन्द्र, राकेश, निकिता, मोहित और देवराज ने भी सभा को सम्बोधित किया। सभा का संचालन कॉमरेड सना ने किया। इसी दिन पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान की भी शुरूआत की गई। इसको लोगों ने भारी समर्थन दिया। काफी महिलाओं हस्ताक्षर किये।

बहादुरगढ़: 23 जनवरी को स्थानीय छोटूराम धर्मशाला में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 115वीं जयन्ती सम्मानपूर्वक मनाई गई। जनसभा की अध्यक्षता कॉ. हरि सिंह दहिया ने की। मुख्य वक्ता डॉ. सूरत सिंह थे। मंच संचालन हरबीर सिंह ने किया। मा. जयकरण, वीरेन्द्र सिंह बेरी, हरबीर सिंह, रवीन्द्र ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने नेताजी के जीवन-संघर्ष से सीख लेकर युवाओं को जाग्रत करने की अपील की। गुरमीत सिंह, सूरजभान, दीपक काद्याण, लालजी व सतीश पसरीजा ने गाने गाए। राणा प्रताप स्कूल के बच्चों ने क्रान्तिकारी गीत व भाषण दिए। सुल्तान सिंह सैनी, धर्मपाल दलाल व अन्यों ने विचार रखे।

बहादुरगढ़ में मशाल जुलूस

सूरत में फोटो प्रदर्शनी

सूरत, गुजरात : 23 जनवरी के दिन नेताजी जयंती पर यहां ए.आई.डी.वाई.ओ. द्वारा एक रैली व स्मृतिसभा का आयोजन किया गया। रैली शहर के मध्य चौक से निकाली गई। शहर के कोने-कोने से आए छात्रों, नौजवानों, मजदूरों तथा महिलाओं ने रैली में हिस्सा लिया। विभिन्न माँगों की पट्टियाँ हाथ में लिए अनुशासित तथा कतारबद्ध रैली जहाँ से गुजरी लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। रैली शहर के चौक से मुगलीसरा होते हुए फुलवारी पहुँची और सभा में बदल गई। सभा के मुख्य वक्ता एस.यू.सी.आई.(सी) गुजरात राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. द्वारिकानाथ रथ थे। सभा की अध्यक्षता ए.आई.डी.वाई.ओ. सूरत के प्रधान कॉ. भीखा भाई प्रजापति ने की। संचालन कॉ. राममूरत मौर्य ने किया। कॉमरेड्स कनु खड़दिया, सत्येन्द्र सिंह, जयेश पटेल, मुकेश सेमवाल, सुरेश मौर्य, तपनदास गुप्ता, प्रयागराज मौर्य, गीता शुक्ला, नवल कुमार झा, युनूस खान पठान, ललित सोलंकी, शफी भाई, सलालुद्दीन इत्यादि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभा की शुरूआत नेताजी की श्रद्धांजली से हुई और समापन कदम-कदम बढ़ाए जा....गीत गाकर किया गया।

फलोदी (राजस्थान) : 23 जनवरी को आजादी आन्दोलन के महान सेनानी व आजाद हिन्द फौज के नायक देशभक्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 115 वीं जयन्ती क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फलोदी के तत्वावधान में सम्मानपूर्वक मनायी गयी।

सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. छाजूराम रावत

नेताजी सुभाष जयन्ती का मुख्य आकर्षण महापुरुषों के शिक्षाप्रद कथनों की उद्धरण प्रदर्शनी रही जिसका उद्घाटन फलोदी विधायक माननीय ओमजी जोशी के कर-कमलों द्वारा हुआ, उन्होंने इस अवसर पर छात्र-युवाओं से आजादी आन्दोलन के शहीदों के जीवन-संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। महापुरुषों के शिक्षाप्रद कथनों की इस आकर्षक उद्धरण प्रदर्शनी को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं ने बड़े उत्साह व चाव से देखा। जनहित की मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान भी इसी दिन प्रारम्भ किया गया तथा फलोदी में शहीदों की प्रतिमाएं लगाये जाने का प्रस्ताव लिया गया।

सभा के मुख्य वक्ता एम.पी. गणेशन थे। शिवकिशन बिस्सा, प्यारेलाल थानवी, यागचंद नागल, अर्जुन चौधरी, गणेश चौधरी, संजय शर्मा, रामगोपाल जांगू, जीवन भील, सूरज वैष्णव, छाजूराम रावत, समस्तदीन मंगलिया, बुद्धाराम चौधरी, देवाराम चौधरी, सिकन्दर घोसी, भरत मेघवाल, हरचंद जयपाल, सुरेश मेघवाल, भैराराम खोरवाल आदि ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर शिक्षाविद् शिवकिशन बिस्सा, यागचन्द नागल, प्यारेलाल थानवी व वयोवृद्ध, वरिष्ठ नागरिक शिवबक्स व्यास, नरसिंगदास बोहरा, कंवरलाल बोहरा, समाजसेवी नीलम जैन, सत्यनारायण, कैलाश व्यास, शहीद मनीषी यादगार कमेटी के छाजुराम रावत तथा छात्र संगठन के श्रवण विश्नोई उपस्थित थे। जयन्ती समारोह का संचालन समारोह संयोजक संगीता रावत ने किया तथा श्रवण विश्नोई ने आगन्तुकों का आभार प्रकट किया।

ढकवा, प्रतापगढ़ (उ.प्र.) : 23 जनवरी को ढकवा प्रतापगढ़, डा. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक शिक्षण संस्थान में आजादी आन्दोलन के गैर समझौतावादी धारा के महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती श्रद्धा-सम्मानपूर्वक मनायी गयी। कार्यक्रम के मुख्य

वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की उत्तर प्रदेश कमेटी के सदस्य कॉमरेड पुष्पेद्र विश्वकर्मा थे। यह कार्यक्रम एआईडीवाईओ के सहयोग और विद्यालय की प्रबन्ध कमेटी की पहल पर हर वर्ष की भाँति हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार यादव ने की। कार्यक्रम की शुरूआत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हुई। विद्यालय के अध्यापक उमाशंकर यादव ने अपने वक्तव्य में नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। विद्यालय के बालक, बालिकाओं व अध्यापकों ने गीत एवं भाषण में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किये जाने के कारण हर वर्ष की भाँति इस वर्ष बच्चों द्वारा रैली नहीं निकाली जा सकी। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं, अध्यापकों, अभिभावकों, के अलावा कॉमरेड्स मनोज कुमार वर्मा, रामप्रसाद विश्वकर्मा, राममूर्ति मौर्य, रामकुमार यादव आदि भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एआईडीवाईओ के राज्य कमेटी सदस्य यशवन्त राव ने किया।

रिवाड़ी (हरियाणा) : 23 जनवरी को एआईडीएसओ और एआईडीवाईओ के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय तुलाराम पार्क से एक सुसज्जित जुलूस निकला जो मुख्य बाजारों से होता हुआ सभा स्थल नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पार्क पहुंचा।

सभा से पहले मुख्य अतिथि एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. राजेन्द्र सिंह द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सभा की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड शेर सिंह ने की। एआईडीवाईओ के जिला सचिव कॉमरेड अनिल कुमार ने मंच संचालन किया। सभा के मुख्य वक्ता एआईडीएसओ की ऑल इण्डिया काउन्सिल सदस्य कॉ. चंचल घोष थे। सभा को एआईडीएसओ के राज्य उपाध्यक्ष कॉ. अजय कुमार और एआईडीवाईओ के जिला कमेटी सदस्य कॉ. करतार सिंह ने भी सम्बोधित किया।

यूपी विधानसभा चुनाव...

(पृष्ठ 4 का शेष)

कह कर कांग्रेस ने अपने को उलझन में डाल लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुस्लिमों के लिए सब-कोटा बढ़ाकर 9 प्रतिशत करने का वायदा करके यह विवाद छेड़ दिया है। प्रसंगवश, कांग्रेस ने अपने 2009 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में ओबीसी मुस्लिमों को आरक्षण देने का वायदा किया था। भ्रष्टाचार से ध्यान हटा कर ''फूटपरस्त राजनीति'' की तरफ फेरने के लिए कांग्रेस पर वार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यह इसलिए है कि 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे से यह अल्पसंख्यकों को आरक्षण कोटा 9 प्रतिशत देने की बात कर रही है और इस तरह ओबीसी के दूसरे तबकों को इससे महरूम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीजेपी ने कभी कहा था कि वह जाटों को आरक्षण देने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हर किसी को यह भी याद होगा कि पूर्व बीजेपी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजस्थान की एक खास जाति की खुशामद करने के लिए जाति के एजेण्डे के पक्ष में बोले थे। आरक्षण के वादों की सवार हुई इस धुन में शामिल होते मुलायम सिंह ने एलान किया कि वे मुस्लिमों को ओबीसी कोष्टक से बाहर 18 प्रतिशत आरक्षण देंगे। उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी कोष्टक के अन्दर मुस्लिमों को 4.5 प्रतिशत सब-कोटा देने के कांग्रेस-नीत केन्द्रीय सरकार के फैसले को ''मामूली'' करार दिया। लेकिन वे इस तथ्य से हकला गये हैं कि यादव व कुर्मी जैसे ''तगड़े'' बैकवर्ड इस सब-कोटे के खिलाफ हैं जो ओबीसी कोटे में उनके 27 प्रतिशत क्रीड़ाक्षेत्र को प्रतिबंधित कर देगा। मुस्लिमों के वास्ते 18 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा करके उन्हें गुमराह करने के लिए मुलायम सिंह की कांग्रेस ने धुनाई की है और उन पर बीजेपी के साथ मिले हुए होने, उत्तर प्रदेश चुनावों में अल्पसंख्यक राजनीति पर डेसिबल लेवल बढ़ाने का आरोप लगाया है। सपा पर कांग्रेस का हमला यू.पी. चुनावों का सब-प्लॉट होना बताया जाता है जहाँ बाजी जीतने के लिए राहुल गाँधी द्वारा एक आक्रामक कोटा राजनीति की अगुआई करने समेत ये प्रतिद्वंद्वी पार्टियाँ मुस्लिमों की वोटों के लिए एक दूसरी से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ''मुस्लिम कोटे'' के लिए ''धर्मनिरपेक्ष'' प्रतिद्वंद्वियों में लगी यह होड़ बीजेपी के लिए उपयोगी हो गई है क्योंकि इसके रणनीतिकारों ने ''पिछड़े'' मुस्लिमों के लिए इस रियायत को हिन्दू ओबीसियों के लिए नुकसान के रूप में चित्रित किया है।

यह याद दिलाना प्रासंगिक होगा कि ब्रिटिश शासकों से राजनैतिक आजादी पाने के समय इन घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़े हुए दलितों के मनों में जायज शिकवे-शिकायतें जमा थी कुछ उपचारात्मक उपायों की व्यवस्था करने के लिए संविधान रचयिताओं पर पब्लिक का दबाव था। इसलिए नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण के एक विशेष प्रावधान को संविधान में जगह मिली। यह आरक्षण सरकारी स्कूल-कॉलेजों, कार्यालयों व सार्वजनिक इकाइयों में लागू था और इसका प्रतिशत कुल आबादी के मुकाबले इन तबकों के लोगों के अनुपात पर आधारित था। ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था। संविधान के रचयिता इस बात से वाकिफ थे कि आरक्षण का यह प्रावधान सदैव के लिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब दलित आबादी के स्थायी पिछड़ेपन को अप्रत्यक्ष मान्यता देना हो जायेगा और यह उन्हें दूसरों के समान स्तर तक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को बाधित कर देगा। मेरिट की तरक्की और समृद्धि के लिए सब के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसी तरह जैसे एक अच्छा छात्र दूसरे बहुत सारे मेरिटोरियस यानी मेधावी छात्रों के साथ प्रतियोगिता करके अपनी दक्षता को पैनी करता है। इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि यह आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा और उसके बाद एक समीक्षा की जाएगी कि सीमित समय के लिए दिया गया यह आरक्षण अपने उद्देश्य को कितनी दूर तक हासिल कर पाया है। लेकिन इस आरक्षण नीति का क्या हश्र हुआ? जिन हितलाभों की परिकल्पना की गई थी क्या वे विशाल संख्यक दलित जनसाधारण को प्राप्त हुए? हर कोई कहेगा कि 'नहीं'। बल्कि इसके विपरीत, आजाद भारत में दूसरे दबे-पिसे लोगों के साथ-साथ उनकी दशा भी बदतर हो गई है।

इसके सिवाय और हो ही क्या सकता था। हमारे जैसे एक वर्ग-विभाजित समाज में शोषकों और शोषितों के बीच, शासक पूंजीपति वर्ग और शासित सर्वहारा वर्ग के बीच परस्पर-विरोधी स्वार्थों के संदर्भ में, सभी व्यक्तियों के विकास के समान अवसरों, सभी तबकों के बच्चों के लिए शिक्षा के बराबर मौके, बेरोकटोक औद्योगिकीकरण के जरिये आर्थिक विकास के द्वारा जनकल्याण व सामाजिक प्रगति और सबको रोजगार दिये जाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए दलितों समेत व्यापक पैमाने पर देशवासियों की आर्थिक व सामाजिक दशा में धीरे-धीरे कोई सुधार लाने की बजाय आजादी के बाद के पूंजीवादी भारत में उनके जीवन के हरेक क्षेत्र में गिरावट और भी तेजी से लाई गई है। पूंजीवाद के नियम के मुताबिक ही, अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सम्प्रदाय के हों। इसलिए हमें यह देखने को मिलता है कि आजादी के 64 साल बाद भी, 60 प्रतिशत दलित अभी भी अनपढ़ हैं। अनुसूचित जातियों के मामले में तो यह अनपढ़ता 70 प्रतिशत है। दूसरी तरफ, आरक्षण के नतीजतन एक छोटे से हिस्से, दलितों का मुश्किल से 3 प्रतिशत ने सभी अवसरों व हितलाभों को हड़प लिया है और वे सभी विशेषाधिकारों व सुविधाओं का मजा लेने वाली 'क्रीमी लेयर' यानी 'मलाईदार परत', सम्पन्न 'अभिजात्यों' की छोटी सी जमात के तौर पर उभर आये हैं और तथाकथित नीची जात वालों के जीवन स्तर में तेजी से आ रही गिरावट के प्रति पूरी तरह निष्ठुर व उदासीन रहते हुए, समाज में हावी मुट्ठीभर अमीरों के हिस्से के तौर पर शक्ति व प्रभाव रखते हैं। इस प्रकार वे असल में पूंजीपतियों के पिछलग्गू बन गये हैं। दलितों में इस मलाईदार परत के उभरने ने एक बार फिर इस हकीकत की तरफ साफ तौर पर ध्यान खींचा है कि पूंजीवाद में वर्ग विभाजन हर पल तेज होता जा रहा है, अमीरों और गरीबों के बीच चौड़ी होती जा रही खाई सामाजिक स्तरीकरण को और भी प्रबल व सुस्पष्ट करती जा रही है। एक कपटी चाल के तौर पर शासक वर्ग ने जनता के सबसे ज्यादा शोषित-पीड़ित वर्ग में से एक सुविधाभोगी ग्रुप को अपने वर्ग-हित के दब्बू बनाने के लिए काट कर अलग कर लिया है और इसे दलित आबादी की 'खुशहाली' के तौर पर पेश किया जा रहा है। जहाँ कांग्रेस और दूसरी पूंजीवादी पार्टियों ने, जो सत्तासीन हुई, समाज की मुख्य धारा में दलितों के उत्थान, जाति-बहिष्कार व अपमानजनक जीवन स्थिति से छुटकारा दिलाने और इस प्रक्रिया में चरणवार आरक्षण की जरूरत को ही खत्म कर देने के लिए कुछ नहीं किया, वहीं पूंजीवादी और निम्न पूंजीवादी पार्टियों की तरफ से, जो इस नारे का इस्तेमाल जनता को उल्लू बनाने और माले मुफ्त व सत्तासुख के लिए फायदेमंद राजनैतिक कॅरियर बनाने के लिए करती हैं, दलितों और अन्य पिछड़े समूहों व समुदायों के लिए फिक्रमंद होने के अपने दिखावे में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। यह बेइज्जती की बात है कि सत्तालोभी राजनैतिक नेता जो प्रतिस्पर्धात्मक कोटे के सुर को पैना करते जा रहे हैं वे महज सत्ता के गलियारों में बने रहने के लिए देश को जातपात, धर्म, भाषा, पंथ और इलाके के आधार पर बांट कर जिस संविधान की सौगंध खाने का दिखावा करते हैं उसी के बुनियादी लक्षणों को पैरों तले रोंद डालते हैं। जहाँ पूंजीवादी नियम और शोषणमूलक पूंजीवादी योजना का अनुसरण करते हुए रोजगार के अवसर संकुचित हो गये हैं, रोजगारों का नुकसान बेतहाशा बढ़ गया है, बेरोजगारी बड़ी भारी बढ़ती जा रही है, सभी सरकारी कार्यालयों में नई भर्ती असल में बंद है और पूंजीवादी व निम्न पूंजीवादी पार्टियाँ आरक्षण को चुनाव में प्रधान मुद्दा बना रही हैं।

राजनेताओं-औद्योगिक घरानों का अन्तर्सम्बन्ध

एक और पहलू हमारे ध्यान से बचना नहीं चाहिए। दलितों, पिछड़े मुस्लिमों और आम तौर पर लुटेपिटों के लिए घड़ियाली आँसू बहाने के बावजूद एक दूसरी से भिड़ रही सभी मुख्यधारा की पूंजीवादी पार्टियाँ स्थापित बड़े पूंजीपतियों के साथ ऑन रिकार्ड 'घनिष्ठ रिश्ते' बनाये हुए हैं जो गरीबों और कंगालों के खून की आखिरी बूंद तक चूस कर तमाम धन-दौलत और खुशहाली पर अपना एकाधिकार कायम करते जा रहे हैं। जैसे कि खबर है, अनिल अम्बानी ने अपने बिजली के बिजनैस और वृद्धि-विकास के अपने साधन को एक मान लिया है और यू.पी. को अपना निर्माण आधार के तौर पर माना है। उसे मुलायम सिंह व उनके कभी नम्बर दो रहे अमर सिंह से बिजनैस रिश्ता और सौजन्य साझा किया है। अम्बानी की योजना का मूलाधार था दादरी में 8,000 मेगावाट का एक गैस आधारित पावर प्लांट लेकिन यह भूमि अधिग्रहण की अवस्था में ही ट्रिप कर गया। मुलायम सिंह की सरकार ने ''जनहित'' का हवाला देकर अम्बानी के लिए 2,500 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। मुलायम सिंह रहते तो उन्होंने बिजली के बिजनैस को कार्यरूप देने में अम्बानी की महत्वाकांक्षाओं को सिरे चढ़ाने का काम और देखा होता-क्योंकि 2012 के अन्त तक 5,000 मेगावाट की योजना पेश की गई थी। रिलायंस पावर 2017 के अपने टारगेट से पीछे है। अगर मुलायम सिंह दोबारा वापस आ जाते हैं तो वह बदल सकता है। अम्बानी के पास दादरी में अभी भी जमीन है, पर गैस नहीं है।

सुब्रत राय की सहारा इण्डिया ने मुलायम सिंह के शासनकाल में बड़े-बड़े भूखण्ड अधिग्रहीत किये थे और 11 टाउनशिपों का एलान किया था, जबकि इसने केवल 2007 में ही इन्हें बनाना शुरू किया था। इस ग्रुप के रियल एस्टेट की जानकारी रखने वाला एक व्यक्ति कहता है कि मायावती के शासनकाल में सहारा ने महज दो प्रोजैक्टों को पूरा किया है। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं, ''अगर मुलायम सिंह सत्ता में रहते तो 6 प्रोजैक्ट पूरे हो गये होते।''

भारत के चीनी के कटोरे, यू.पी. में चीनी निर्माता भी मुलायम सिंह का नाम श्रद्धा-सम्मान से लेते हैं। मुलायम सिंह के शासनकाल में कुशाग्र बजाज ने अपनी क्षमता पाँचगुनी बढ़ा ली थी, यहाँ तक कि उनमें से कुछ नये प्लांटों का उद्घाटन तो मुख्यमंत्री ने ही किया था। युवा कुशाग्र बजाज की अगुआई में हुए इस विस्तार से देखा गया कि यह एक समय की अग्रणी क्षमता वाली बलरामपुर चीनी मिल्स के गढ़, पूर्वी यू.पी. में भी जबरन जा घुसा है।

मुम्बई आधारित चीनी की दलाली से वास्ता रखने वाले चीनी के मामले के एक विश्लेषक अपना नाम नहीं बताना चाहते हुए कहते हैं, ''अमर सिंह के बाहुबल ने उनकी (कुशाग्र बजाज की) अपनी वित्तीय ताकत के साथ मिल कर बजाज को नम्बर एक स्थान हासिल करने में मदद की।''

मार्च, 2009 में मायावती सरकार ने यू.पी. में 6,000 करोड़ रुपये का शराब का व्यवसाय एक औद्योगिक समूह को सौंपने का फैसला लिया था। टेण्डर प्रक्रिया से चुना गया यह समूह गुरूदीप सिंह चड्ढ़ा का था जो पोंटी चड्ढ़ा के नाम से बखूबी जाने जाते हैं। लाइसेन्स देने की नीति के बारे में आरोप लगा है कि इसे पोंटी चड्ढ़ा के लिए पूर्णरूप से उपयुक्त बनाया गया। यह समूह नोएडा के केन्द्रस्थल पर 152 एकड़ की कमर्सियल जमीन को भी विकसित कर रहा है जहाँ इतने बड़े भूखण्ड मिलने मुश्किल हैं। लेकिन उसने यू.पी. में ऐसे लाखों बनाये, पहले मुलायम सिंह के शासन में जिन्होंने लखनऊ में उसके वेव माल-कम-मल्टीप्लैक्स का उद्घाटन किया था और फिर मायावती के शासन में। सन 2010 में उसने यू.पी. में बिकी 11 में से 5 बीमार चीनी मिलों को अपनी झोली में डाल लिया था। खबर है कि उसे ये मिलें 276 करोड़ रुपये में मिल गई थी, जबकि उनका बाजार भाव उस समय 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये था। यह जिक्र करने की शायद ही कोई जरूरत है कि

(शेष पृष्ठ 8 पर)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly
Date of Printing : 5 February, 2012

यू.पी. विधानसभा चुनाव...

(पृष्ठ 7 का शेष)

कांग्रेस और बीजेपी को चोटी के एकाधिकारी पूंजीपति घरानों से खुला समर्थन प्राप्त है और इसने या तो सूबे में या सेंटर में उन पार्टियों के शासनकाल में इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिए क्या गुल खिलाये हैं।

नकली मार्क्सवादियों की मौकापरस्ती

जहाँ शासक पूंजीपति वर्ग के वर्ग स्वार्थ को आज्ञाकारी ढंग से पूरा करने के काम लिए बंधी हुई पार्टियों से घोर धोखेबाज जनविरोधी भूमिका अदा किया जाना बिल्कुल अपेक्षित था, वहीं सीपीएम, सीपीआई व उनके सहयोगी दलों जैसी नकली मार्क्सवादी पार्टियों की विश्वासघाती भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जब लोग जातिवादी-साम्प्रदायिक राजनीति के शिकार हो रहे हैं और बुरी तरह से धोखा खाने और पीठ में छुरा घोंपा जाने के लिए चुनावों में कभी एक पार्टी या गठबंधन और कभी दूसरी किसी पार्टी या गठबंधन के बीच झूल रहे हैं, तब उन्नत नीति-नैतिकता पर आधारित न्यायसंगत जनवादी जनआन्दोलन को बढ़ावा देने की वाम-जनवादी राजनीति की एक वैकल्पिक धारा छेड़ना और इस चल रहे जनवादी आन्दोलन के हिस्से के तौर पर चुनावों में हिस्सा लेना वक्त का तकाजा था। महज जीतने की गरज से किसी से भी सिद्धांतहीन गठजोड़ करने या येन केन प्रकारेण सीटें हथियाने पर फोकस हरगिज नहीं होना चाहिए बल्कि जनान्दोलन को मजबूत करने, लोगों की राजनैतिक चेतना बढ़ाने और विधानपालिका में लोगों की माँगों के लिए निडरता के साथ आवाज उठाने के लिए जितने ज्यादा हो सकें जनवादी जनआन्दोलन के तपे-तपाये सेनानी वहाँ भेजने पर फोकस होना चाहिए। संसदीय आन्दोलन को संसद के बाहर होने वाले आन्दोलनों के साथ समन्वित करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। और कुछ नहीं बल्कि जनहित बाकी सारे सोच-विचारों पर भारी पड़ना चाहिए। दरअसल बेशरम घोर भ्रष्ट सुविधा-पिपासु धोखाधड़ी की बुर्जुआ राजनीति को कोई असली चुनौती नहीं दी गई है। लेकिन सीपीएम, सीपीआई आन्दोलन के इस रास्ते से कोसों दूर हैं। वामपंथ का लबादा ओढ़ कर–मीडिया की मेहरबानी से–अपने एमएलए, एमपी की संख्या बढ़ाने के लिए इस या उस पूंजीवादी पार्टी या गठबंधन से सीटों में विपथगामी हिस्सेदारी पर उतर आती हैं। विधानपालिकाओं के अन्दर उनके और दूसरी पार्टियों के एमएलए, एमपीओं की भूमिका और आचरण-व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं होता है। शासक वर्ग के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देने के बाद, यह वह गिरावट है जो उन्होंने दर्ज कराई है। जहाँ तक जनविरोधी, पूंजीपतिपरस्त नीतियों को अपनाने और न्यायसंगत जन आन्दोलनों को बेरहमी से कुचलने का सवाल है, उनके द्वारा चलायी गई राज्य सरकारों को किसी दूसरी सरकार से कोई फ़र्क दर्शाया नहीं जा सका है। हर किसी को याद होगा कि साढ़े चार साल तक कांग्रेस-नीत प्रथम यूपीए सरकार का समर्थन करने के अलावा इन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में भ्रष्टाचार की महारानी के तौर पर जानी जाने वाली जयललिता से हाथ मिलाया था। आन्ध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में इन्होंने तेलंगाना अलगाववादी आन्दोलनकारियों से भी गठजोड़ किया था। 2009 के लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने तथाकथित तीसरे मोर्चे की प्रधानमंत्री के तौर पर मायावती को प्रोजैक्ट करने की बात की थी। इस बार जब वे केरल और पश्चिम बंगाल, दोनों में ही सत्ता से हटा दी गई हैं, तो यू.पी. में उनको लेने वाला कोई नहीं है। अगर अपने गैर वामपंथी रवैये और कार्यकलापों को सुधारने की तरफ उनका जरा भी झुकाव रहा होता तो वे लोगों का जनवादी आन्दोलन खड़ा करने के साझे कार्यक्रम के आधार पर तमाम वामपंथी ताकतों को एकजुट करने का आह्वान कम-स-कम दिया होता और एक वामपंथी विकल्प के तौर पर चुनावों में हिस्सा लिया होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे ऐसी कोई गतिविधि करने के अनिच्छुक हैं जो शासक वर्ग को नाराज कर दे और इसके आशिर्वाद और पृष्ठपोषण से दोबारा वापसी की सम्भावनाओं पर पानी फेर दे। यह समझा जाता है कि वे बुर्जुआ राजनीतिज्ञों के झुण्ड में शामिल होने, चढ़ते सूरज को नमस्कार करने के लिए बेताब हैं और विधानसभा में किसी तरह एक दो उम्मीदवार खिसका लाने की सम्भावना तलाशने के लिए अभी भी किसी भी ताकत के साथ स्थानीय स्तर पर जोड़तोड़ करने की फिराक में हैं। लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस बार वे किसके पिछलग्गू बनने वाले हैं।

चुनावों में आन्दोलन की सच्ची ताकत को मजबूत करें

इसलिए यह साफ है कि यू.पी. नकली मार्क्सवादियों समेत पूंजीवादी और निम्न पूंजीवादी पार्टियों की फूटपरस्ती और लोगों की खिल्ली उड़ाने की गंदी राजनीति का अखाड़ा हो गया है। इस घिनौनी जातपातवादी औ साम्प्रदायिक राजनीति के जाल में फंसा, बेरहम पूंजीवादी शोषण के जुए तले कराह रहा और इस दमघोंटू स्थिति से छुटकारा पाना चाह रहा आम आदमी पूरी तरह घाटे में है, इससे निजात पाने का रास्ता ढूंढ़ रहा है। बचने का रास्ता हर तरह की फूटपरस्ती व संकीर्णता से ऊपर उठ कर और उच्चतर नीति-नैतिकता व संस्कृति के आधार पर जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर सही नेतृत्व में सचेत एकताबद्ध दीर्घस्थाई संगठित जनवादी जन आन्दोलन के विकास-वृद्धि में है। लेकिन इस सच्चाई पर पर्दा पड़ा हुआ है। गद्दारी, विश्वासघात की यह गंदी राजनीति, सत्तालोभियों के बीच चल रही भीषण होड़ की यह शक्ल-सूरत, लगातार बदली जा रही जातिगत और साम्प्रदायिक वफादारी और कई दूसरी अकल्पनीय बातें इस वांछित जन आन्दोलन के विकास की प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं। वक्त आ गया है जब यू.पी. के दुख पा रहे लोगों को यह अत्यावश्यकता आत्मसात करनी होगी, शर्मनाक जातिगत और साम्प्रदायिक राजनीति के चंगुल से बाहर निकलें और अपने जीवन संघर्ष को सही रास्ते पर निर्मित करें। उन्हें इन होने जा रहे चुनावों को भी इसी नजरिये से देखना होगा, मौकापरस्त, वोट-केन्द्रित सत्तालोभी पार्टियों व गुटों को जनता से अलग-थलग करें और इस जन आन्दोलन को खड़ा करने के लिए और इसलिए जनहित के लिए प्रतिबद्ध ताकतों को तहेदिल से अपना समर्थन दें। वे अपने तजुर्बे से जानते है कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) वह आन्दोलन की पार्टी है, लोगों की सही माँगों को गुलंद करने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरी रहती है, शासक वर्ग और उसके भाड़े के टट्टुओं के हमलों से नहीं डरती है, चाहे सत्ता में कोई बैठा हो उसके गुस्से में लाल-पीले हो जाने से यह डरने वाली नहीं है। लोग देखते आ रहे हैं कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)ने किसी चीज की ऐवज में अपना जमीर कभी नहीं बेचा है, लुभावने संसदवाद के जाल में कभी नहीं फंसी है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कभी नहीं किया है। जहाँ बाकी सब माले मुफ्त और सत्ता-सुख पाने के लिए राजनीति में हैं, वहीं एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)क्रान्तिकारी राजनीति की महानता को कायम रखने के लिए मैदाने जंग में है जो इसके उन्नत नैतिक व सांस्कृतिक स्तर में गहरी रची-बसी हुई है क्रूर पूंजीवादी दमन-उत्पीड़न के क्लेश से लोगों की मुक्ति के लिए कुर्बानी देना, जीवन समर्पित कर देना सिखाता है। बार-बार यह मेहनतकश लोगों का ध्यान इस बात की तरफ दिलाती आ रही है कि उनकी एकता को तोड़ने के लिए शासक वर्ग तरह-तरह की रंगतों वाली अपनी ताबेदार राजनैतिक पार्टियों की मदद से जातिवादी और साम्प्रदायिक लाइनों पर लोगों में फूट के बीज बो रहा है, उन्हें हरी-हरी घास दिखा कर बेवकूफ बना रहा है और इस तरह उन्हे सतत विनाश की तरफ ध केल रहा है। अपनी सांगठनिक ताकत के आधार पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) इस स्पष्ट राजनैतिक लाइन को लेकर आठ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि विधान सभा में लोगों की आवाज गुंजाना सुनिश्चित करने के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के उम्मीदवारों को वोट दें और जितायें।

यू.पी. विधानसभा चुनावों में एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवारों की सूची

जिला	निर्वाचन क्षेत्र	उम्मीदवार
जौनपुर	जाफराबाद	कॉमरेड श्रीपति सिंह
	बदलापुर	कॉमरेड प्रबोधकुमार शुक्ला
सुलतानपुर	लम्भुआ	कॉमरेड जयप्रकाश मौर्य
प्रतापगढ़	पट्टी	कॉमरेड राजमणि विश्वकर्मा
कानपुर	कल्याणपुर	कॉमरेड वालेन्द्र कटियार
मुरादाबाद	मुरादाबाद शहर	कॉमरेड इस्लाम अली
भीमनगर	असामौह	कॉमरेड शील कुमार
बलिया	रसारा	कॉमरेड अनिल कुमार

...संसद अभियान की तैयारी जोरों पर

(पृष्ठ 3 का शेष)

मुख्यालय मंगलौर आदि महत्वपूर्ण कस्बों से गुजरा।

अभियान के दौरान नुक्कड़ सभाएं व नुक्कड़ नाटक किये गये। प्रधानमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किये और इस आन्दोलन के लिए दिल खोल कर चन्दा दिया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी की राज्य कमेटी के दो सदस्यों कॉमरेड बी.आर. मंजूनाथ और एच. जी. जयललिता ने जत्थे का नेतृत्व किया और जगह-जगह हुई सभाओं को सम्बोधित किया। ''कम-से-कम एक पार्टी तो है जिसने इन असल मुद्दों को उठाया है!'' यह टिप्पणी पार्टी की एक सभा में शामिल हुए एक आदमी की थी।

रोहतक, हरियाणा :

आम सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती

29 जनवरी को स्थानीय छोटूराम पार्क के हाल में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)की राज्य स्तरीय जनरल बॉडी मीटिंग हुई। इसका संचालन पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने किया। पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान, राज्य कमेटी के सदस्यों, पार्टी के जिला सचिवों और जनसंगठनों के राज्य सचिवों के अलावा कई अन्य कॉमरेडों ने 14 मार्च को दिल्ली चलो कार्यक्रम की जोरशोर से चल रही तैयारी में हस्ताक्षर संग्रह और प्रचार अभियान की रिपोर्ट पेश करते हुए अनेक मूल्यवान सुझाव दिये। अन्त में कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम की जरूरत और अहमियत पर बोलते हुए कार्यक्रम को जोरदार सफल बनाने की पुरजोर अपील की।

गुजरातः

अहमदाबाद में जन ज्ञापन पर हस्ताक्षर संग्रह और प्रचार अभियान में जुटे एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाषः 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com